

शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रावधानों और दिशानिर्देशों का अनुपालन का अध्ययन

कुमारी ममतेश सोलंकी¹, डॉ. महीप कुमार मिश्रा²

¹रिसर्च स्कॉलर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

²प्रोफेसर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

सारांश

इस विश्लेषण में SMC की संरचना, कार्यप्रणाली, और चुनौतियों का तथ्यात्मक अध्ययन किया गया है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि किस प्रकार SMC शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, ड्रॉप-आउट दर को कम करने, और स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के विकास में योगदान दे सकती है। साथ ही, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में SMC की भूमिका और उनके सामने आने वाली समस्याओं की भी समीक्षा की गई है। यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि SMC की सक्रियता और सही दिशा में प्रयास, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन, SMC को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सदस्यों की प्रशिक्षण की कमी, वित्तीय संसाधनों की सीमाएं, और प्रशासनिक समर्थन का अभाव। इन समस्याओं को हल करके, SMC शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अतः, स्कूल प्रबंधन समितियों की उचित सशक्तिकरण और समर्थन न केवल शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज में शिक्षा की गुणवत्ता और साक्षरता दर को भी बढ़ावा देगा।

मुख्य शब्द: अधिनियम, संरचना, कार्यप्रणाली, चुनौतियों, सीमाएं

परिचय

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम) 2009 को अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे 1 अप्रैल 2010 से कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया था।

आरटीई अधिनियम 2009 ने बहुत बहस पैदा की है। एक तरफ, इसका विरोध किया गया है और स्कूली शिक्षा को और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए नव-उदारवादी राज्य की योजना के रूप में इसकी निंदा की गई है, वहीं दूसरी तरफ इसे सबसे क्रांतिकारी अधिनियम के रूप में देखा गया है। हालाँकि, दोनों ही स्थितियाँ वास्तविकता से बहुत दूर हैं। जहाँ पहली स्थिति अधिनियम के पूर्ण विरोध और सरकार के साथ टकराव की ओर ले जाती है, वहीं दूसरी स्थिति वर्तमान भारतीय राज्य की वास्तविक मंशा और क्षमता के बारे में निष्क्रियता और भ्रम की ओर भी ले जा सकती है। दोनों में से कोई भी स्थिति जन शिक्षा के उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारा मानना है कि अपनी सीमाओं के बावजूद, आरटीई अधिनियम के कुछ प्रावधान जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बढ़ी हुई भूमिका, अगर सही तरीके से उपयोग की जाए, तो देश में आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले लगभग बंद हो चुके सरकारी स्कूलों को

पुनर्जीवित करने की क्षमता है। इन प्रावधानों को नागरिक समाज के ठोस हस्तक्षेप और केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों के साथ रचनात्मक जुड़ाव के माध्यम से साकार किया जा सकता है।

भारत में सरकारी स्कूल प्रणाली गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, जो भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। यह हमारे देश की कुल 860 मिलियन आबादी का 77 प्रतिशत है।¹ उन्हें उपलब्ध शिक्षा की अत्यंत खराब गुणवत्ता यह सुनिश्चित करती है कि भारत के अधिकांश बच्चे अभी भी बहुत पीछे हैं। हमारे स्कूलों की सार्वजनिक प्रणाली की ऐसी निराशाजनक स्थिति का एक मुख्य कारण यह है कि स्थानीय समुदाय खुद को मुखर करने और वांछित परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हैं।

यह विडंबना है कि शिक्षा एक महान समतलीकरण हो सकती है और मौजूदा सामाजिक विभाजन को कायम रखने का एक साधन भी हो सकती है। भारत में स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में बहुत अधिक पदानुक्रम मौजूद है। स्कूल तक पहुँच के मामले में अवसर की समानता, केवल एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह गई है। भारत का मध्यम वर्ग जो अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन कर सकता है, अपने बच्चों को उच्च शुल्क वाले निजी स्कूलों में भेजना पसंद करता है और बाकी लोगों के लिए खराब ढंग से सुसज्जित और मुश्किल से काम करने वाले सरकारी स्कूल ही एकमात्र विकल्प हैं। समाज में मौजूद सामाजिक और आर्थिक विभाजन स्कूलों तक पहुँच में भी परिलक्षित होता है।

सरकार द्वारा संचालित स्कूल प्रणाली विषम है और इसमें बहुत विविधता है। एक तरफ, हमारे पास एकल शिक्षक, कम बहु-ग्रेड ईजीएस स्कूल हैं और दूसरी तरफ, आराम से वित्त पोषित - केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं जो सीमित बच्चों (सरकारी कर्मचारियों के) को लक्षित करते हैं। इनमें भारत के अधिकांश स्कूल हैं जो सरकार द्वारा प्रबंधित और वित्त पोषित हैं और भारत के ग्रामीण परिदृश्य में बिखरे हुए हैं।

आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अभिभावकों को उनके द्वारा चुने गए एसएमसी के माध्यम से कुछ अधिकार सौंपे गए हैं; इनका उचित प्रयोग स्कूलों में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसे वास्तविक रूप देने के लिए, बड़े पैमाने पर समुदाय और विशेष रूप से एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से समर्थन दिया जाना चाहिए। उन्हें आरटीई अधिनियम के प्रावधानों, भूमिकाओं, संरचना और एसएमसी के गठन की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

साहित्य की समीक्षा

मकमुन (2023) इस अध्ययन का उद्देश्य SMK Negeri 2 Metro में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में स्कूल समितियों की भूमिका का विश्लेषण और वर्णन करना है। यह शोध एक केस स्टडी डिज़ाइन के साथ गुणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। शोध डेटा को गहन साक्षात्कार तकनीकों, अवलोकन और सूचनादाताओं के साथ दस्तावेज़ीकरण अध्ययनों द्वारा एकत्र किया गया था: SMK Negeri 2 Metro के स्कूल समितियाँ, प्रिंसिपल, शिक्षक, पर्यवेक्षक और छात्रों के माता-पिता। डेटा विश्लेषण डेटा में कमी, डेटा प्रस्तुति और निष्कर्ष के माध्यम से किया जाता है। डेटा की वैधता की जाँच करने के लिए विश्वसनीयता, निर्भरता और पुष्टि के साथ किया जाता है। परिणामों से पता चला कि समिति के गठन में कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का उल्लेख किया गया था और इसमें शिक्षक परिषद, समुदाय, सरकार और व्यापार और औद्योगिक दुनिया के तत्व शामिल थे। स्कूल समिति की प्रमुख भूमिका विचार और समर्थन के प्रावधान से संबंधित है, जबकि नियंत्रक के रूप में समिति की भूमिका अभी भी स्कूल के बजट के उपयोग में सीमित है और शैक्षणिक मुद्दों और स्कूल के प्रदर्शन के मूल्यांकन पर कम ध्यान देती है। इसी तरह, मध्यस्थता की भूमिका हितधारकों द्वारा समर्थित है, यह देखते हुए कि SMK कई तत्वों के साथ सहयोग करता है। एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्कूल समिति SMK नेगेरी 2 मेट्रो में गुणवत्तापूर्ण

शिक्षा को साकार करने में बहुत मददगार है। निष्कर्ष में, सहायता प्रदाता के रूप में स्कूल समिति की भूमिका को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में लागू किया गया है, जिसमें शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे और बजट के लिए समर्थन के रूप में शामिल है।

मित्तल, कुंजना. (2020). शिक्षा राष्ट्र की आत्मा है और इसके बिना राष्ट्र सांस नहीं ले सकता। इस प्रकार शिक्षा राष्ट्र की नींव है। यह लोकतंत्र के समग्र विकास और सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति के कौशल और व्यक्तित्व का विकास करती है और उसके विकास का अर्थ है राष्ट्र का विकास। शिक्षा के कई उद्देश्य हैं जैसे रोजगार, मानव संसाधन का समग्र विकास और सामाजिक वातावरण में बहुत जरूरी बदलाव लाना, जिससे समग्र प्रगति हो। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सशक्तीकरण की ओर ले जाता है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। इसे समाज की नींव के रूप में देखा जाता है जो आर्थिक संपदा, सामाजिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता को सक्षम बनाता है। शिक्षा व्यक्ति की छत, रोटी, कपड़ा के बाद चौथी बुनियादी जरूरत है। शिक्षा राष्ट्र के विकास या प्रगति के लिए प्रभावी उपकरण है। यह समाज को विकसित करने की मूल जड़ है। शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने का एक साधन है।

आज़ाद, यश. (2024). शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के जीवन को उपयोगी और सार्थक तरीके से निर्देशित करना है। समाज में व्यक्ति की सफलता के लिए शिक्षा को आवश्यक माना जाता है। भारत में शैक्षिक विकास का मार्ग इसके इतिहास में गहराई से निहित है। भारतीय शिक्षा प्रणाली प्राचीन शिक्षा प्रणाली से लेकर मध्यकाल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली तक विभिन्न चरणों में विकसित हुई है। 21वीं सदी के वैश्वीकरण में, दृश्य-श्रव्य साधनों में नवाचार और सीखने और शिक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी की मांग ने सीखने और शैक्षिक वातावरण को गुरुकुल की प्राचीन विधियों से सीखने के नए क्षितिज में बदल दिया है।

परिवर्तनों के साथ-साथ नई अपेक्षाएँ और चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। स्वतंत्र भारत में हमारी शिक्षा का पहला लक्ष्य आकांक्षी का समग्र विकास करना था। पाठ्यक्रमों में नैतिक मूल्यों की कमी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तेजी से बदलती तकनीक, शिक्षा का व्यावसायीकरण, निजीकरण और शैक्षिक गुणवत्ता में कमी, विविध सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय क्षेत्रों के कारण संचार की कमी, लिंग असमानता, महिला साक्षरता दर का कम होना, ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद, अल्पसंख्यक समूहों के साथ भेदभाव, बुनियादी ढांचे की कमी, परिवहन की गुणवत्ता की शिक्षा केवल एक सपना लगती है। भारतीय संविधान ने शिक्षा के अधिकार सहित छह मौलिक अधिकारों की स्थापना की, साथ ही अनुच्छेद 45 में छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता का प्रावधान किया। शैक्षिक प्रणाली को पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा अंतिम स्थान पर है। हालाँकि, इस प्रणाली में कई खामियाँ और खामियाँ हैं, जिन्हें यदि संबोधित किया जाए, तो शिक्षा के इच्छुक व्यक्ति के समग्र विकास को लाभ हो सकता है। इसलिए।

शोध उद्देश्य

1. विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा वित्तीय और गैर-वित्तीय संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका का मूल्यांकन।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रावधानों और दिशानिर्देशों का अनुपालन का मूल्यांकन।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अध्ययन में प्रयुक्त अनुभवजन्य जांच के लिए शोध डिजाइन का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें प्रयुक्त शोध दृष्टिकोण और प्रयुक्त डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण विधियों का विस्तृत विवरण शामिल है।

समस्या का अध्ययन करने के लिए एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया था। इस जनसंख्या में से केवल 50% स्कूलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था, इन चयनित स्कूलों में से छह स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। एसएमसी सदस्यों द्वारा वास्तव में निभाई जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एसएमसी सदस्यों के लिए प्रश्नावली विकसित की गई थी। इस उपकरण में आरटीई अधिनियम के अनुसार किए जाने वाले विभिन्न कार्यों पर 24 आइटम शामिल थे। इसकी सामग्री की वैधता की जांच करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा उपकरण को मान्य किया गया था। प्रश्नावली के प्रशासन से पहले सभी चयनित एसएमसी सदस्यों को अध्ययन के उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में बताया गया था। डेटा का प्रतिशत का उपयोग करके मात्रात्मक रूप से विश्लेषण किया गया था। प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को आवृत्तियों में परिवर्तित किया गया और फिर प्रतिशत में उनका रूपांतरण किया गया।

वर्तमान अध्ययन में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले को प्रशासनिक इकाई के रूप में चुना गया है। हापुड़ जिले के चार विकास खंडों के विभिन्न वर्गों से 450 उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। एक अनुसूची के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका के बारे में इन उत्तरदाताओं के विचार, राय और विचारों को जानने का प्रयास किया जाएगा। अनुसूची के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद उनका विश्लेषण किया जाएगा और निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए इन आंकड़ों का गहन विश्लेषण करके सहसंबंध परीक्षण किया जाएगा।

अनुभवजन्य जांच की व्याख्या

तालिका-5.1 'स्कूल विकास योजना' तैयार करने के संबंध में एसएमसी सदस्यों की अनभिज्ञता।

सामान	को प्रतिशत	
	नहीं	कह नहीं सकते
एसएमसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले 'एसडीपी' तैयार करती है।	34	66
एसडीपी में प्रत्येक वर्ष कक्षावार नामांकन का अनुमान शामिल होता है।	34	66
एसडीपी में तीन वर्ष की अवधि में प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अध्यापकों सहित अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या की आवश्यकता शामिल है। अध्यापकों.	34	66

तालिका-5.2 'स्कूल विकास योजना' तैयार करने के संबंध में एसएमसी सदस्यों की अनभिज्ञता।

सामान	प्रतिशत	
	नहीं	कह नहीं सकते
एसडीपी में तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भौतिक आवश्यकता शामिल है।	34	66
एसडीपी में तीन वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता शामिल है।	34	66
'एसडीपी' वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है।	34	66

तालिका-5.1 और 5.2 से स्पष्ट है कि 34% एसएमसी सदस्यों को 'स्कूल विकास योजना' के बारे में पता था, इसके बावजूद उन्हें 'स्कूल विकास योजना' तैयार करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 34% एसएमसी सदस्यों का मानना था कि एसएमसी ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले 'स्कूल विकास योजना' तैयार नहीं की थी, उनके एसडीपी में प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का अनुमान शामिल नहीं था, उनके एसडीपी में तीन साल की अवधि में प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक शिक्षक सहित अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या की आवश्यकता शामिल नहीं थी, उनके एसडीपी में तीन साल में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भौतिक आवश्यकता शामिल नहीं थी, उनके एसडीपी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि 66% एसएमसी सदस्य 'स्कूल विकास योजना' के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने 'स्कूल विकास योजना' के बारे में कभी कुछ नहीं सुना।

जांचकर्ताओं ने एसएमसी सदस्यों से 'स्कूल विकास योजना' तैयार न करने के पीछे के कारणों के बारे में पूछा। जवाब तालिका संख्या 5.3 में प्रस्तुत हैं:

तालिका-5.3 'स्कूल विकास योजना' तैयार न करने के पीछे के कारणों पर एसएमसी सदस्यों की प्रतिक्रियाएँ

'स्कूल विकास योजना' तैयार न करने के पीछे के कारणों पर एसएमसी सदस्यों की प्रतिक्रियाएँ	प्रतिशत
सरकार एसडीपी के बारे में ऐसी जानकारी नहीं देती है।	68
एसडीपी की तैयारी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है।	32

तालिका संख्या 5.3 से पता चलता है कि 68% एसएमसी सदस्यों का मानना था कि सरकार एसडीपी के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान नहीं करती है, इसलिए वे आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसडीपी तैयार नहीं कर सके। जबकि, 32% एसएमसी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि एसडीपी तैयारी के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, इसलिए वे आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार एसडीपी तैयार नहीं कर सके।

सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका डेटा एकत्र करने के लिए तीन श्रेणियों की प्रश्नावली का उपयोग किया गया, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और छात्र तथा एसएमसी सदस्यों के लिए साक्षात्कार अनुसूची। तालिका 5.4 उत्तरदाताओं द्वारा प्रश्नावली वापसी दर दर्शाती है।

तालिका 5.4 उत्तरदाताओं की प्रश्नावली वापसी दर

उत्तरदाताओं	अपेक्षित प्रतिक्रिया	वास्तविक प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया दर प्रतिशत (%)
प्रधानाध्यापक/शिक्षक	25	25	100
शिक्षक	175	170	97.1
विद्यार्थियों	375	346	92.3
एसएमसी सदस्य	125	105	84
कुल	700	646	92.3

तालिका 5.4 के परिणामों से पता चला कि प्रधानाध्यापकों के लिए प्रश्रवली वापसी की दर कुल मिलाकर 100% थी, शिक्षकों के लिए 97.1%, विद्यार्थियों के लिए 92.3% और एसएमसी सदस्यों के लिए 84% थी क्योंकि शोधकर्ता ने सभी उत्तरदाताओं को प्रश्रवली के वितरण में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था।

निष्कर्ष

स्कूल प्रबंधन टीम पर राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से आने वाली सामाजिक मांगों के कारण पाठ्यक्रम परिवर्तन के कार्यान्वयन का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। इसमें सफल होने के लिए, स्कूल प्रबंधन टीमों को पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम परिवर्तन को लागू करने के लिए उन्हें कौन सी प्रमुख भूमिकाएँ निभानी होंगी। अनुभवजन्य जांच से यह स्पष्ट हो गया कि स्कूल प्रबंधन टीम के प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रबंधन से संबंधित उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। सफल पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रबंधन के प्रमुख बाधा प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् अपर्याप्त कक्षाएँ और शिक्षण सुविधाएँ और कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता, स्कूल प्रबंधन टीमों को पाठ्यक्रम परिवर्तन के कार्यान्वयन के जिम्मेदार और जवाबदेह सुविधाकर्ताओं के रूप में, लगातार समस्याओं के क्रमिक सक्रिय समाधान के लिए संवेदनशील होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम परिवर्तन के कार्यान्वयन के प्रबंधन के साथ प्रासंगिक सफलता की धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि में योगदान दे सकता है।

संदर्भ

- [1]. काशाबावा, बाला और यूसुफ, आइशा। (2016)। ज़मफ़ारा स्टेट बेसिक स्कूलों में स्कूल-आधारित प्रबंधन समिति की रणनीतियाँ और बुनियादी ढाँचागत विकास। ट्रॉपिकल एजुकेशनल मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। पहला संस्करण। 96-115।
- [2]. नचिंगुरू, जॉर्ज और मविला, प्रॉस्पेरी। (2023)। वित्तीय संसाधन प्रबंधन: किनोनडोनी नगर पालिका, तंजानिया में सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयों में स्थिति और चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च। 1. 1-14. 10.61421/IJSSMER.2023.1101।
- [3]. न्गोवी, निकोलस और चाचा, पॉलिना और माफ़वोलो, जेम्मा। (2022)। तंजानिया में स्कूल प्रबंधन समितियों के प्रदर्शन की प्रभावशीलता का आकलन: इलेमेला नगर पालिका के चयनित सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों से साक्ष्य। 5. 70-88।
- [4]. वुरिआंडोको, सैंटोसो और पुरवती, श्री और सुगियार्तो, सुगियार्तो और नूरकोलिस, नूरकोलिस। (2024)। प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की पूर्ति और शिक्षा वित्तपोषण के प्रबंधन के लिए रणनीति। परिप्रेक्ष्य इल्मु पेंडिडिकन। 38. 94-103. 10.21009/पीआईपी.381.9.
- [5]. ओनेस्मो अमोस (2021), “माध्यमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान में स्कूल प्रमुखों के वित्तीय प्रबंधन कौशल की प्रभावशीलता,” इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च वॉल्यूम 9 नंबर 3 मार्च 2021
- [6]. मोमानी, एरिक और थिंगुरी, रूथ और ओगोची, जॉर्ज। (2022)। किरिन्यागा वेस्ट सब-काउंटी, किरिन्यागा काउंटी, केन्या में पब्लिक प्राइमरी स्कूलों में योग्यता आधारित पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर स्कूलों के प्रबंधन की वित्तीय तैयारी का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल फॉर इनोवेशन एजुकेशन एंड रिसर्च। 10. 1-15. 10.31686/ijer.vol10.iss10.3558।
- [7]. शर्मा, आब्रीति. (2021). सिक्किम में स्कूल प्रबंधन समितियाँ: सरकारी अधिकारियों की धारणा पर एक अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ हेल्थ साइंसेज. 495-503. 10.53730/ijhs.v5nS1.10614.

- [8]. चेतोचि, मिलिसेंट और एटोनी, रोज़ और मुनुआ, जेनिफर। (2020)। केन्या के पश्चिम पोकोट काउंटी के कपेंगुरिया निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयों में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए रणनीतियों की खोज। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स (IJSRP)। 10. 153-159. 10.29322/IJSRP.10.10.2020.p10623.
- [9]. एफेंडी, रुसदी और फितरिया, हैप्पी और नूरखालिस, नूरखालिस। (2020)। शिक्षा की गुणवत्ता पर स्कूल समिति और स्कूल संचालन निधि की भूमिका का प्रभाव। जर्नल ऑफ़ सोशल वर्क एंड साइंस एजुकेशन। 1. 194-203. 10.52690/jswse.v1i2.48.
- [10]. परवेज, राव और यूसुफ, एम. और परवीन, कैसरा और कंवल, वजीहा और तैयब, एम. (2015)। जिला झंग में प्राथमिक स्तर पर स्कूल प्रबंधन पर स्कूल प्रबंधन समितियों का प्रभाव (एक केस स्टडी)। साइंस इंटरनेशनल। 28. 3115-3118।
- [11]. गैस्पर, मिल्ली और गेब्रियल, जोसलीन और मैनुअल, मैनुअल और लैड्रिलो, डिविना और गेब्रियल, इवांगेलिन और गेब्रियल, अर्नील। (2022)। स्कूल वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन की पारदर्शिता और जवाबदेही। जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। 12. 102. 10.5296/jpag.v12i2.20146।
- [12]. सैटी, सैटी. (2023). स्वतंत्र शिक्षण युग में स्कूल की समिति की भूमिका. पीपीएसडीपी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन. 2. 244-251. 10.59175/pijed.v2i2.90.
- [13]. एज़ेह, चिनयेरे और ओगारा, पॉलिनस। (2020)। एनुगु शिक्षा क्षेत्र में प्रभावी स्कूल प्रशासन पर वित्तीय प्रबंधन का प्रभाव। बहुभाषी शैक्षणिक जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज। 7. 1-15।
- [14]. हर्नांडेज़, मेलानी। (2024)। बुनियादी शिक्षा सेवाओं के वितरण में माध्यमिक विद्यालय प्रशासकों की स्कूल संसाधनों और वित्तीय क्षमताओं का प्रबंधन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसिप्लिनरी: एप्लाइड बिजनेस एंड एजुकेशन रिसर्च। 5. 3155-3165. 10.11594/ijmaber.05.08.18.